



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 कार्तिक 1944 (श०)

(सं० पटना 895) पटना, मंगलवार, 25 अक्टूबर 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

5 सितम्बर 2022

सं० 7/मुक0-08-08/2022 सा०प्र०/15840—माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या—4242/2022 (एस०एल०पी०(सी०) संख्या—10776/2021), आरव जैन बनाम बिहार लोक सेवा आयोग एवं अन्य साथ में सिविल अपील संख्या—4243/2022 (एस०एल०पी०(सी०) संख्या—11089/2021), संजय कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल अपील संख्या—4244/2022 (एस०एल०पी०(सी०) संख्या—15809/2021), सुमित कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल अपील संख्या—4246/2022 (एस०एल०पी०(सी०) संख्या—15819/2021), मयंक कुमार पाण्डेय उर्फ मयंक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, सिविल अपील संख्या—4245/2022 (एस०एल०पी०(सी०) संख्या—16198/2021), आशीष चन्द्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या—4247/2022 (एस०एल०ए०(सी०) संख्या—809/2022), अनिता कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.05.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में 30वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (वि०सं०—06/2018) के परीक्षाफल के विरुद्ध बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक—८/वि०प्र०—०४—०५/२०१७(०६)ल०से०आ०/गो० दिनांक 17.06.2022 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में निम्न ०८ (आठ) अभ्यर्थियों को बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम—२४ के तहत परीक्ष्यमान रूप में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर रु० 27700—770—33090—920—40450— 44700/- के वेतनमान में समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	जन्म तिथि	लिंग	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण कोटि
1	2	3	4	5	6	7
1	125499	मयंक कुमार पाण्डेय	15	20.02.1990	पुरुष	01
2	100345	आरव जैन	21	23.07.1987	पुरुष	01
3	125441	आशीष चन्द्रा	62	03.09.1991	पुरुष	01
4	114020	सिद्धार्थ शर्मा	104	03.02.1993	पुरुष	01
5	109002	संजय कुमार मिश्रा	157	01.01.1986	पुरुष	01
6	110721	अनिता कुमार	584	04.01.1978	महिला	02
7	106878	सुमित कुमार	533	05.11.1990	पुरुष	04
8	103270	आनन्द राज	417	09.08.1991	पुरुष	05

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या-4242-4247/2022 में दिनांक 23.05.2022 को पारित न्यायादेश की कडिका-18 एवं 19 के निम्नांकित शर्तों के अधीन यह नियुक्ति की जा रही है:-

18. In the above arrangement, we make it clear it would not affect the appointment/selection of already serving Judicial officers appointed against Advertisement No. 6 of 2018.

19. The eight appellants would be entitled to their respective seniority as per their merit; however, they would not be entitled to any arrears of salary for the intervening period, but would be entitled to the same from the date of their joining. They would be forthwith allowed to join. All incremental and other benefits of the intervening period would be notionally available to them, but no arrears would be paid.

3. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पें को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन नियुक्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

6. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2017 में बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 के नियम 25(ख) में विभागीय अधिसूचना संख्या-7/स्था0-1-4-05/2011 साप्र03245 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार "असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व सेवा छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।"

7. अभ्यर्थी को फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

8. नियुक्ति पत्र में अंकित नवनियुक्त परीक्ष्यमान न्यायिक पदाधिकारियों की सेवायें माननीय उच्च न्यायालय, पटना को पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।

9. योगदान किये जाने हेतु उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 895-571+10-डी०टी०पी०

Website: <http://egazette.bih.nic.in>